

एक लाख महिलाओं को बनायेंगे लखपति दीदी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगातों की समीक्षा की



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर जनता को दी जाने वाली सौगातों की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में समीक्षा की।

जयपुर, 6 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार "आपणो अग्रणी राजस्थान" की दिशा में निरंतर बढ़ते हुए अपनी पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें देकर उनका सशक्तिकरण करेगी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा नवाचार एवं कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं मजदूरों सहित विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए दूरगामी कार्य किए जाएंगे।

शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि दिसम्बर माह में, वर्षगांठ के अवसर पर भवन एवं अन्य संनिर्माण से जुड़े 1.5 लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही, 2 हजार दिव्यांग जनों को स्कूटी वितरित की जाएगी और प्रत्येक जिले में कैम्प लगाकर 10 हजार निःशक्तजनों को सहायक सामग्री व सहायता उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पालनहार योजना के अंतर्गत, लगभग 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपये की राशि भी हस्तांतरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। इससे महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ेगी और वे विकसित

राज्यस्थान के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगी। शर्मा ने कहा कि अन्नदाताओं के समग्र विकास के लिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर राजस्व विभाग द्वारा 9000 पटवारियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे।

इस दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, प्रमुख सचिव राजस्व दिनेश कुमार सहित, संबंधित विभागों के शासन सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राहुल गाँधी ने महाराष्ट्र चुनाव में संविधान को मुद्दा बनाया

नागपुर, 6 नवम्बर। कांग्रेस नेता राहुल गाँधी अपना नैरेटिव लेकर महाराष्ट्र के मंदान में उतर आए हैं। राहुल लोकसभा चुनाव वाला ही नैरेटिव विधानसभा चुनाव में चलाना चाहते हैं इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र में अपने कैम्पेन की शुरुआत नागपुर से की। वो सबसे पहले दीक्षाभूमि पहुंचे जहां बाबा साहेब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। यहाँ राहुल गाँधी ने अंबेडकर को

उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से दलितों, ओ.बी.सी. व आदिवासियों के साथ अन्याय का पता चलेगा

श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। राहुल गाँधी ने कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना जरूर होगी और इस प्रक्रिया से दलितों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा।

नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गाँधी ने कहा, "जाति जनगणना से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हर किसी को पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी ताकत है और उनकी भूमिका क्या है।" गाँधी ने कहा, "हम 50 प्रतिशत (आरक्षण सीमा) की दीवार भी तोड़ देंगे।"

'बिना पूर्व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) मुख्य न्यायाधीश ने आज कहा कि इस मामले में ध्वस्तीकरण बिना किसी सूचना के किया गया।

उन्होंने कहा, "यह तो स्पष्ट है कि यह ध्वस्तीकरण निरंकुशतापूर्ण था तथा यह कानून की सत्ता को अबाधित था। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह ध्वस्तीकरण केवल इसलिये किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता ने सड़क-निर्माण में हुई अनियमितताओं की रिपोर्ट एक अखबार में प्रकाशनाथ भेज दी थी। राज्य सरकार की ऐसी कार्यवाही का समर्थन या अनुमोदन नहीं किया जा सकता तथा निजी सम्पत्ति के मामले में तो कानून का पालन होना ही चाहिये।"

नीट-यूजी 2024 परीक्षा दुबारा नहीं होगी

सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने समीक्षा याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 6 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2 अगस्त के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से नीट-यूजी 2024 परीक्षा को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने मामले पर खुली अदालत में सुनवाई के अनुरोध को भी ठुकरा दिया। यह याचिका काजल कुमारी ने दायर की थी। कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि इसकी परीक्षा दोबारा नहीं होगी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाय चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उसके फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। रिकॉर्ड को देखते हुए कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के आदेश के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए, समीक्षा याचिका

राहुल के "अतिवाद" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कर रहे हैं जो कांग्रेस का ठोस वोट-बैंक हैं तथा देश के जन मत-निर्माता (ओपिनियन मेकरर्स) भी हैं।

पार्टी नेताओं का दृढ़तापूर्वक कहना है कि राहुल गाँधी को एक ऐसा बीच का रास्ता तलाश करने की जरूरत है, ताकि वे अपने राजनैतिक विचारों की विसंगतियों को ठीक कर सकें, जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन राहुल न तो एक परिपक्व और पक्के राजनेता हैं और न ऐसे मंजूर हुए कलाकार हैं, जो मौके के अनुसार, अपने शब्दों का चालाकी से गोलमोल इस्तेमाल करते हुए, कलाकारी से, नाटकीयता से काम ले सकें।

सूत्रों का कहना है कि पार्टी, गरीबों, दलितों तथा पिछड़ों के प्रति उनकी चिन्ताओं को पसन्द तो करती है, उनकी कद्र भी करती है, लेकिन उनकी यह चिन्ता कांग्रेस को चुनाव जीतने में सदैव मदद नहीं कर सकती।

उदाहरणार्थ, हरियाणा में पूरा दलित समाज कांग्रेस को छोड़कर चला गया, जबकि राहुल उनकी खातिर, उनके भले के लिये एक मशाल उठाये हुये थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में, संविधान के मुद्दे तथा ओ.बी.सी.,

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ विशेष सेंटरो पर लीकेज की बात सामने आई है, इसके लिए पूरे देश की परीक्षा रद्द करना व्यवहारिक नहीं है।

मिश्रा की पीठ ने कहा कि उसके फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। रिकॉर्ड को देखते हुए कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के आदेश के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए, समीक्षा याचिका

खारिज की जाती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2004 परीक्षा दोबारा कराने से इन्कार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था, कुछ विशेष सेंटरो पर ही लीकेज की बात सामने आई थी इसलिए पूरे देश की परीक्षा रद्द करना व्यवहारिक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेपर लीकेज पूरे देश में नहीं था सिर्फ दो जगहों तक ही सीमित था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह नीट-यूजी 2024 को फिर से आयोजित करने का आदेश नहीं दे सकता क्योंकि उसके रिकॉर्ड में कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है जो प्रणालीगत लीक या धांधली का संकेत देती हो।

उदयपुर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कार के नीचे से बैठे श्वान को घसीटकर ले जाने लगा। घायल श्वान की आवाज सुनकर आसपास के अन्य श्वान वहां पर पहुंच गए और भौंकाते लगे, इस पर तेंदुए की अपनी जान अचाकर मौके से भागना पड़ा और शिकार करने में सफल नहीं हो पाया। यह पूरी घटना चौक के एक मकान में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद हो गई। तेंदुए ने आबादी क्षेत्र में, जहां यह हमला किया, वहां चारों तरफ घेर दिये।

बताया जा रहा है कि घटना स्थल से करीब डेढ़ किमी दूर सज्जनगढ़ अभयारण्य है, जहां लैपर्ड का मूवमेंट रहता है। इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने बुधवार को दो पिंजरे खवा दिए हैं, ताकि दुबारा इस इलाके में प्रवेश करने पर तेंदुए को रोक्यु किया जा सके।

दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं

यमुना का पानी प्रदूषित होने के कारण एक हजार जगह छठ पूजा का इंतजाम किया गया है

'झारखंड में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बताती है कि तीसरा बिन्दु "साम्प्रदायिक आधार पर बाँटने वाली सामग्री" से सम्बन्धित है, जिसमें हिन्दू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है। इस प्रकार के एक वीडियो में दिखाया गया है कि हरे रंग के कपड़े पहने मुस्लिमों का एक ग्रुप तलवारें लहराते हुये, भगवा कपड़े पहने एक हिन्दू पुरुष का पीछा कर रहे हैं। इस वीडियो के अन्त में यह कैप्शन आता है - "बैंटिंगे तो कटेंगे। संगठित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।" चौथे बिन्दु में उन खतरों की बात की गई है, जो इस क्षेत्र में घुसपैठियों के आने से पैदा होने वाले हैं।

यद्यपि झारखंड भाजपा इकाई इन शैडो अकाउन्ड्स द्वारा किये जा रहे खर्च से तीन गुने से ज्यादा खर्च कर रही है तथा इन अकाउन्ड्स से तीन गुने ज्यादा विज्ञापन दे रही है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत कम हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है - "भाजपा की झारखंड इकाई विज्ञापन पर एक रूपया खर्च कर रही है तथा शैडो नेटवर्क भी एक रूपया ही खर्च कर रहा है, लेकिन शैडो नेटवर्क की पोस्टों को पार्टी के विज्ञापन की तुलना में चार गुना से ज्यादा लोग देखते हैं।" रिपोर्ट आगे कहती है - "एक समान घनराशि में, शैडो पेज ज्यादा सामग्री दे रहे हैं और वह ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। यह चीज राजनैतिक विज्ञापनों एवं प्रचार के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की रणनीतियों के बारे में गम्भीर प्रश्न उठा रही है।

घड़ी चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी और कहा था कि अजीत गुट सार्वजनिक रूप से घोषणा करेगा कि घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल सिर्फ लोकसभा चुनाव में होगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल अदालत में विचाराधीन है।

एन. सी. पी. में विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा में संख्या बल के आधार पर अजीत गुट को असली एन. सी. पी. स्टार देकर चुनाव चिन्ह दे दिया था।

शरद पवार गुट को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी-शरद चंद्र पवार नाम दिया था और "तुरही बजाता व्यक्ति" चुनाव चिन्ह दिया था।

'बुद्धिजीवियों का राजनीतिक सोच...'

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बार हाईलाइट करने से लोग आर्थिक अनिश्चितता की बात पर यकीन करने लगे। आर्थिक समस्याओं को लोगों के दिमाग में जोर-शोर से बिठा दिया गया, जिस पर लोग विश्वास करने लगे।

इससे वो कहावत सत्य साबित होती है कि सबसे बड़े झूठ को भी यदि बार-बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मानने लगेंगे। डॉनल्ड ट्रम्प ने इस आइडिया का पूर्ण रूप से फायदा उठाया है, क्योंकि उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान अपने अनेक असत्यों को अनेकों बार दोहराया।

इसी तरह, डॉनल्ड ट्रम्प ने औसत श्वेत अमेरिकी नागरिक के इस डर का लाभ उठाया कि अनियंत्रित इमिग्रेशन (अप्रवासन) आबादी के संतुलन पर दबाव बना रहा है। उदाहरण के लिए, ट्रम्प ने एक प्रचार बैठक में कहा था कि लैटिन अमेरिकन देशों के अप्रवासी लोग उनके (अमरीकियों के) पालतू जानवरों को खा रहे हैं। इसके तुरंत बाद भारी

हंगामा शुरू हो गया था तथा पाया गया कि यह आरोप पूर्णतया असत्य था। परंतु अमेरिका के दक्षिण से लगतार अप्रवासियों का आना एक सच्चाई थी तथा सीमा से लगे कुछ शहरों में आबादी की संरचना बदल रही थी। जाहिर है कि इमिग्रेशन मुद्दे को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी का अधिक मानवीय दृष्टिकोण आम आदमी को रास नहीं आया। ये मुद्दे इमिग्रेशन या अर्थव्यवस्था या गर्भपात का अधिकार अमेरिकी उदारवादी व्यवस्था के मुख्य सिद्धांतों के विरुद्ध थे, जिनका प्रतिनिधित्व वहाँ का अभिजात्य वर्ग और बुद्धिजीवी करते हैं। अमेरिकी मतदाताओं का यह अमीर व समृद्ध वर्ग उम्मीद कर रहा था कि

अमेरिका की राजनीति में कमला हैरिस उनके उदारवादी मूल्यों को आगे बढ़ाएंगी। अपने आप को "मिडिल क्लास" (मध्यम वर्ग) तथा "कलर्ड" के रूप में दर्शाने के कमला हैरिस के प्रयासों ने इन उपरोक्त वर्गों को लोगों को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि इस बार अश्वेत मतदाता हैरिस के साथ नहीं थे। इस बार अश्वेत मतदाताओं ने ट्रम्प का साथ दिया। इसी के साथ, यह स्वीकार करना होगा कि कमला हैरिस ने दबंग डॉनल्ड ट्रम्प के विरुद्ध बहुत बहादुरी का प्रदर्शन किया। वो ट्रम्प, जिन्होंने सत्य और नैतिक मूल्यों में जरा भी विश्वास नहीं दिखाया। हैरिस को लगभग आधे

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदूषित नदी के पानी में पर्व मनाने से बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत खराब हो सकती है।

इसलिए यह बैन लगाया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि यमुना में डुबकी लगाने से लोगों की तबियत खराब हुई है। यहां तक कि उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ गया है। ऐसे में इस याचिका पर किसी भी

ट्रम्प की वापसी भारतीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) को या तो नया बाजार ढूँढना होगा और फिर अमेरिका के सामान पर जवाबी कर लगाना होगा या फिर समझौता करना पड़ेगा।

श्रीवास्तव ने आगे कहा कि ट्रम्प ने आउटसोर्सिंग पर चिन्ता जताई थी हालांकि उनकी कुछ बातें चुनाव से जुड़ी हैं पर भारत को उन कदमों के लिए तैयार रहना होगा जो आई.टी. निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं। एच-वन बी वीजा, जो कि आई.टी. प्रोफेशनल्स के अमेरिका जाने पर रोक लगा सकता है। ट्रम्प की कठोर इमिग्रेशन नीति भारतीय आई.टी. कंपनियों को भारी पड़ सकती है।

दूसरी ओर ट्रम्प लेबर व पर्यावरण स्टैंडर्ड में सुधार कर सकते हैं जिससे

तरह का आदेश देने से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

कोर्ट ने यमुना के बढ़ते प्रदूषण पर भी चिन्ता जताई और कहा- हम नदी में सोबेज छोड़ना जारी नहीं रख सकते। यह इंडस्ट्रियल सोबेज नहीं है, बल्कि सोबेज है। नदी के किनारे अवैध कालोनियाँ बनाई गई हैं। इनका अनट्रैटेड सोबेज नदी में जा रहा है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि नदी में मौजूद प्रदूषण को हटाना भी जा सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह काम रातों रात संभव नहीं है।

भारतीय निर्यात को फायदा होगा। ट्रम्प भारत पर अमेरिका के साथ ज्यादा निकट सम्बंध का दबाव डाल सकते हैं। राजनैतिक लक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दवा के क्षेत्र में सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका विस्तार हो सकता है पर इससे भारत की विदेश नीति की फ्लैक्सिबिलिटी सीमित हो जाएगी। इसके अलावा अमेरिकन कंपनियों के लिए भारत एक प्रमुख आकर्षण है खासकर प्रोफेशनल्स सर्विस, निर्माण व आई.टी. क्षेत्र में। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा इन्वैस्टर है अप्रैल 2000 से जून 2024 तक अमेरिका भारत में 66.7 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है और भारत से अमेरिका को भारी इन्कम होती है सिर्फ व्यापार से ही नहीं बल्कि गृहल, फेसबुक एवं एमेज़ॉन के जरिए भी।

लोकप्रिय वोट मिले, हालांकि, इलेक्टोरल कॉलेज के चरण में ये ट्रम्प के पक्ष में चले गए।

दूसरा, हैरिस के पास एक जबरदस्त प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए समय बहुत कम था। बाइडन चुनाव मैदान से बड़ी देर से बाहर हुए, तब तक वो डेमोक्रेटिक पार्टी के अभियान को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके थे।

इन चुनाव परिणामों से एक और चौंकाने वाला उदाहरण सामने आया है कि बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया, वास्तविकता व राजनीति का आकलन आम आदमी के आकलन से मेल नहीं खाता है। इससे यह बात भी लगभग साबित होती है कि "पॉपुलर वोट" परिणाम लगभग हमेशा ही बुद्धिजीवियों और अभिजात्य वर्ग के विरोध में जाते हैं। सर्वोच्च स्तर के अमेरिकी मीडिया तथा लगभग समस्त पश्चिमी जगत ने एक समान रूप से ट्रम्प का विरोध तथा हैरिस का समर्थन किया था। लेकिन जनता के मन में कुछ और ही था।